को राजी है। हम एक दो लाख फारेन एक्सचेंज उस के लिए लगा रहे हैं। तो जब अप टु डेट टेक्नोलाजी चीनी मिल में हम लगाएंगे तो जंगलों की कटाई कागज के लिए नहीं होगी और अखबारी कागज जो हम यहां पैदा करेंगे उस को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 15 से 20 परसेंट तक हम इस में बगास में बचत कर सकते हैं और उस के लिए अखबारी पेपर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्यों कि दुनिया के अन्दर बगासे की टेक्नोलाजी केवल क्यूबा के पास है। उस से यह टेक्नोलाजी ले कर जब बगास से पेपर हम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से यह हमारे लिए काफीअच्छी चीज होगी। हमारे यहां कुछ गैस सीजनल लेबोरेटरीज हैं। उन लेबोरेटरीज से क्या हमारा काम आज नहीं बनता है? एनर्जी कंजर्वेशन में हम उस से काफी आगे काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा काम इस क्षेत्र में कर सकते हैं इस के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक आखिरी सुझाव होगा।

जहां तक पावर का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में नान-कन्वेन्शनल एनर्जी के लिए प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। हमने सब्सीडी कम कर दी है और इन्सेंटिव कम कर दिए हैं—यह नहीं करना चाहिए। पिछले तथा अगले कमिटमेन्टस को पूरा करने के लिए इस प्लान में हमें ज्यादा पैसे का प्रावधान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि देश में अमीर और गरीब के बीच में जो अन्तर है उसको कम किया जाना चाहिए और यही प्लानिंग का उद्देश्य होना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, परन्तु मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि ऐसे अधिकांश अवसरों पर अर्थशास्त्रियों में परस्पर उतनी ही मतभिन्नता होती है, जितना कि उनमें परस्पर मतैक्य होता है। जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष जो वस्तुतः प्रश्न उठता है वह है आर्थिक आयोजनाओं के लिए उन राजनैतिक विकल्पों को चुनना जो अर्थशास्त्रियों ने हमें दिए हैं। यह एक पूर्णतया आर्थिक कार्य के साथ-साथ उतना ही राजनैतिक कार्य भी है, क्योंकि अन्ततः हम देश के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं।

मैं गांधी जी का एक उद्धरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था :

> "आपने जो सबसे निर्धन तथा कमजोर व्यक्ति देखा है उसके चेहरे का स्मरण करके अपने आप से पूछो, यदि आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम से क्या उसे लाभ होने जा रहा है।"

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है। हमने

इस बात पर जोर दिया है कि सबसे निर्धन व्यक्ति आत्म-निर्भर बन सके और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास। यह योजना न केवल केन्द्रीय सरकार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि हमारे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व करती है, तथा इस कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लगन तथा मेहनत से हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है जो उन उद्देश्यों को परिभाषित करती है जिन्हें हमने आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्र के समक्ष रखे हैं। इस दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में आम-राय से तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो हम देश को देना चाहते हैं। प्रत्येक योजना को एक विशिष्ट समय में व्याप्त समस्यायों पर ही ध्यान देना चाहिए। समस्यायें भी वैसे ही बदलती रहती हैं जैसे कि विकास में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि नई समस्यायें आती रहती हैं। लेकिन इन समस्यायों का समाधान करने में हम पंडितजी तथा इन्दिराजी के वचनवद्धता से अलग नहीं हुए हैं और इस योजना में हमने पंडितजी तथा इन्दिराजी के बताए गए रास्तों पर जोर दिया है तथा वही रास्ता अपनाया है ? हमारी योजना प्रक्रिया की उपलब्धियों को यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है, तथापि हमारे एक माननीय विपक्षी सदस्य ने जो कहा है उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :

"छठी पंचवर्षीय योजना असफल रही है।"

मैं अब इस पर टिप्पणी करने जा रहा हूं।

छठी पंचवर्षीय योजना हमारी सफलतम योजनाओं में एक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

दो मिनट बोलने दीजिए..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

छठी पंचवर्षीय योजना शायद हमारी सबसे सफलतम योजना रही है। पिछली किसी योजना की तुलना में इसमें औसत विकास की दर 5% से अधिक हुई है और यह उपलब्धि हमने विकास, वित्तीय तथा आर्थिक मोर्चों पर जबरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों के दौर के दौरान प्राप्त की है। भारत विश्व के उन थोड़े से देशों में है जो पिछड़ेपन के प्रति बेपरवाह नहीं रहे। वस्तुतः, हमारा कार्य पहले से बेहतर रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अभिप्राय है असफलता। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 1980 में 52 प्रतिशत से घटकर 1984 में 37 प्रतिशत हो गई। माननीय सदस्य अनुभव कर सकते हैं कि यह असफलता है। शायद वह गरीबी रेखा को 52 प्रतिशत रखना चाहते हैं इसके नीचे.....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पूरे देश में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आंकड़े के आधार पर आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं, परन्तु वास्तविक रूप में नहीं।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्यों को लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखने में निहित स्वार्थ है, जबकि हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। उनका निहित स्वार्थ उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखने में है, ताकि वे सरकार की आलोचना कर सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री राजीव गांधी : किन्तु प्रमाण कथनी से होता है। हमने देश को दिखा दिया है कि जो आश्वासन हम देते हैं, उनका पालन करते है और इस सभा के बाहर जो हमारे मित्र बैठे हैं, उनसे मैं सादर कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि हम इस सभा में बैठे हैं और वे सभा के बाहर हैं। जब हम छठी पंचवर्षीय योजना पर बात-चीत कर रहे थे तब हमने देखा था कि महान योजनाकार इस सभा के बाहर थे……

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम योजनाकार नहीं हैं, बल्कि हम तो नौसिखियां हैं।

श्री राजीव गांधी :…1977-78 में अचानक योजना में गिरावट आने लगी। योजना में गिरावट आने के साथ देश भी अवनति की ओर अग्रसर हुआ।

1952 से ही हमारी योजना ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एक विकासशील देश किस प्रकार तरक्की करता है, किस प्रकार एक विकासशील देश विशिष्ट क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भर बन सकता है तथा विकास कर सकता है। हमें न केवल योजनाकारों को धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि अपने वैज्ञानिकों, तकनीशीयनों, अपने किसानों तथा मजदूरों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद करना चाहिए……

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह तो ठीक है।

श्री राजीव गांधी : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। केवल कांग्रेस सरकार के दिशा-निर्देश तथा मार्गदर्शन के कारण ही यह सम्भव हो सका है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हमारे समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं—वे हैं गरीबी हटाना, सामाजिक न्याय दिलाना तथा आत्म-निर्भर बनना। वास्तविक प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे करेंगे। इसका मूल आधार तो हमारी पुरानी नीतियां ही रहेंगी। परन्तु हमें उन नीतियों, उन विचारों को आज के भारत के अनुरूप लागू करना पड़ेगा। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना पर एक नजर दौड़ाए तो हमें पता चलेगा कि उस समय भारत कैसा था तथा आज का भारत कैसा है, कितना जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन योजना के कारण हो सका है, और पंडित जी के इस

समय के विचारों को आज के भारत में लागू करते समय हमें आज के भारत के अनुरूप ही उसे लागू करना होगा। हम उस समय के भारत के लिए अपनाए गए उनके तरीके को अब तीस वर्षों के पश्चात यथावत रूप में नहीं अपना सकते। परन्तु उनका विचार तथा सिद्धान्त आज भी ठीक है। वह आज भी उतना ही लाभप्रद तथा प्रासंगिक है, बशर्ते कि हम उसका इस्तेमाल आज के संदर्भ में तथा इस अवधि में योजनाओं के कारण हुए विकास को ध्यान में रखते हुए करें।

पंडितजी ने कहा था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करनी होगी। विकास का यही आधार बनेगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निःसन्देह, हम केवल उपयुक्त प्रौद्योगिकी चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है। जो हमारे लिए उपयुक्त है वह कदाचित् उस व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त होगा जो ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसे अब बिल्कुल जरूरत नहीं।

हमें यह देखना होगा कि हम अपनी आवश्यकता के लिए अच्छी-सी अच्छी प्रौद्योगिकी प्राप्त करें। सर्वप्रथम सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी हमें उस क्षेत्र के लिए प्राप्त करनी पड़ेगी जहां हम अधिकतम विकास करना चाहते हैं।

हमें इसका आरम्भ कृषि तथा किसानों से करना पड़ेगा। हमारे किसान प्रौद्योगिकी के बिना प्रगति नहीं कर सकते। देश के कुछ भाग में हरित क्रान्ति के क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि वहां उन्हें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई। अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसे उपलब्ध करानी पड़ेगी।

इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम उन व्यक्तियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं जो ऐसे संसाधनों के उपयोग करने के अभ्यस्त हो गए हैं जो उनके पास उपलब्ध है।

कृषि के लिए केवल यही प्रश्न नहीं है कि किसानों को अथवा उन्नत किस्म के बीज, अथवा बेहतर मौसम सूचना उपलब्ध कराई जाए, बल्कि हमें जल प्रबंध संबंधी प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा हम इस प्रकार करेंगे कि किसान कम उर्वरकों का प्रयोग करके बेहतर फसल उगा सकें ? जल का कम उपयोग करके बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? एक तरफ तो हमें अपने संसाधनों का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि करनी है।

ये दो बातें तभी हो सकती है यदि हम सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, भारत में आज भी किसान के सामने शायद सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानसून समय पर आता है अथवा वह दस दिन विलम्ब से आता है या समय से पहले आ जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब हमारे पास उपग्रह है। वह (किसान) टेलीवीजन

सेट चला सकता है, वह देख सकता है कि बादल छाये हैं या नहीं। उसे मालूम है कि पांच दिन में बादल आ जायेंगे। फिर यह जानकारी शत प्रतिशत सही नहीं है, हमारे पास उसे पक्के तौर यह जानकारी देने की क्षमता होनी चाहिए कि इतने दिनों के भीतर मानसून अथवा वर्षा आ सकती हैं जिससे उसे इस बारे में जानकारी हो सके और तदनुसार अपने खेतों को जोतें और दी गई जानकारी के अनुसार तैयार रहें।

इसके लिए केवल एक रास्ता है। हमें सर्वाधिक परिष्कृत सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करना होगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। यह कहना बिलकुल गलत होगा कि उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी किसान के लिए नहीं हो सकती है। किसान को खेत जोतने के लिए दो बैल और बेहतर किस्म का हल दे देने का आशय समुचित प्रौद्योगिकी नहीं है। हमें यह देखना है कि लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए हमारा लक्ष्य उनके जीवन यापन की स्थिति को ऊंची उठाना है। इस प्रयोग के लिए हमें प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी है। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसकी शुरुआत किसान से हो। पानी और उर्वरकों जैसी साधारण चीजों के बेहतर उपयोग के लिए हमारे पास सर्वाधिक परिष्कृत जानकारी हो। हो सकता है हमें ऐसे किसी सस्ते ठोस मिट्टी परिक्षण उपकरण की आवश्यकता हो जिससे उसे यह पता लग सके कि एक बोरी अमुक उर्वरक डाले और अमुक उर्वरक न डालें। कुछ साधन हों जो उसे यह बता सकें कि आने वाले चार दिनों तक वह पानी का प्रयोग न करें।

आजकल इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। हमारे किसानों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए इसको सस्ते मूल्य पर विकसित किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रोद्योगिकी के विकास पर हमें जोर देना होगा। शहरी क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र भी शीघ्रता से बढ़ता है, उसकी समृद्धता और अन्य मांगे भी बढ़नी शुरू होती है और तब इसका लाभ हमारे सारे उद्योग तक पहुंचेगा।

उसके बाद हमें लघु क्षेत्र पर जोर देना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में इसके बाद सबसे अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

इसी प्रकार हमें यह देखना होगा कि नयी प्रौद्योगिकी से लघु क्षेत्र को लाभ किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार लघु क्षेत्र को दूसरे बड़े आकार अथवा बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। हमें उस बात पर जोर देना होगा कि लघु क्षेत्र में लगे हमारे सभी लोगों को बड़े उद्योगो में खपाया जा सके, कुटीर उद्योगों के लोग लघु क्षेत्र में आयें और नये लोग कुटीर उद्योगों को शुरू करें। इस प्रकार की वृद्धि यहां पर होनी चाहिए। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को लघु क्षेत्र में बांध दे और किसी व्यक्ति को कुटीर उद्योग तक ही सीमित रखें और कहें कि यदि तुम प्रगति करते हो अथवा तुम्हारा उत्पादन निर्धारित सीमा से 5 रुपया बढ़ जाता है तो अचानक कर भारों से लाद दिये जाओगे इससे सारी प्रणाली अव्यावहारिक हो जायेगी। किसी भी प्रणाली में कुछ विकास क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

आवास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी भी जरूर होनी चाहिए। हमारी आवासीय व्यवस्था

अभी भी काफी खर्चीली है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मकान की कीमत किस प्रकार कम की जा सकती है। इसे एक सीमा तक कम किया जाना चाहिए। जिससे औसत आदमी को आवास मिल सके, मकान बहुसंख्य लोगों को उपलब्ध हो और यह सुविधा शहरी क्षेत्रों और कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुछ धनाढ्य लोगों को, जो इन्हें खरीद सकते हैं तक ही सीमित न रहे। इस क्षेत्र में हमने कोई कार्य नहीं किया है। अभी भी हमारे मकान ऐसे ही बनते हैं जैसे आज से ठीक बीस-तीस वर्ष पहले बनते थे। इस क्षेत्र में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है।

आलोचनात्मक क्षेत्रों में शिक्षा भी है, हमारे शिक्षा प्रणाली बहुत उपयोगी है। यहभारत में महान वैज्ञानिक पैदा करने में सहायक रही है। इसने सर्वोत्तम शिल्पवैज्ञानिकों को पैदा करने में मदद की है। हमारी शिक्षा-प्रणाली से प्रत्येक क्षेत्र में हमारे यहां महान व्यक्ति पैदा हुए हैं लेकिन आज विकास में नाटकीय परिवर्तन हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्र के उस भार को वहन करने के लिए या तो तैयार नहीं हैं अथवा असमर्थ है जो इस पर डाला जा रहा है। शिक्षा प्रणाली की इस कमी अथवा प्रणाली में लचीलेपन के अभाव के कारण आध्यात्मिक विकास और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के बीच हम भारी खाई पैदा कर रहे हैं। हमारी प्रणाली इस खाई को पाटने के लिए बनाई जानी चाहिए तभी हमें वास्तव में देश और मानवजाति के हित के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने योग्य हो, सकेंगे। यदि यह खाई और बढ़ती है तब हम प्रौद्योगिक के गुलाम हो जायेंगे और हमारा काम करने के लिए प्रौद्योगिकी हमारी गुलाम नहीं होगी। यह एक ऐसा आलोचनात्मक क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक सोच विचार, वाद-विवाद और विचार-विमर्श की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति इन विचारों को फलित करेगी।

सातवीं योजना के हमारे लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारा उद्देश्य एक समाजवादी समाज और एक ऐसे समाज का विकास करना है जो सबको समान अवसर देता है। एक ऐसा समाज जहां पर असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है, अपने आप से जकड़े एक निष्क्रिय समाज के स्थान पर एक गतिशील समाज का विकास करना है। इसे भी शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

हमने हाल में कुछ मंत्रालयों को मिलाकर एक किया है और उन्हें "मानव संसाधन विकास" का नाम दिया है हमने ऐसा केवल दिखावे के लिए नहीं किया है। वास्तव में हम मानव संसाधनों का विकास करना चाहते हैं। आज प्रत्येक कोने से लोग चिल्ला रहे हैं कि जनसंख्या के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने देश में इस सबसे बड़ी समस्या को सबसे बड़े संसाधान में बदल देना चाहते हैं। हमें यही करना चाहिए उन्हें केवल प्रौद्योगिकी विज्ञान या औबाधि अथवा काई अन्य विषय पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका विकास करना है। उनके भीतर नैतिक मूल्यों और आदर्श की भावना का विकास करना है, देश के प्रति समर्पण की भावना, हमें जो संस्कृति के विरासत

मिली है उसका विकास करना है। इन सभी को एक सूत्र में पिरोना है । हम इन बातों को स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकते और परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि आज भारत में हमारी पम्पराएं हमारी विरासत, और संस्कृति है वह निष्क्रिय न रहे। हम प्रायः इस बात की चिन्ता करते हैं यह ऐसा नहीं है जैसा प्राचीन पुस्तक में कहा गया है। हमें आगे के कार्य में भी सोचना चाहिए। हमने विकास भी करना है। हमारी संस्कृति हमारी कला, हमारे संगीत और हमारे नृत्य की तरह रही है, हमारी संस्कृति वही है जैसा हमारा रहन-सहन है। यह हमारी कला है, यह हमारा संगीत है, यह हमारा नृत्य है, लेकिन इसमें पान चबाना भी शामिल है। इसमें वे सब बातें भी शामिल हैं जिन्हें हम गलत समझते हुए भी करते हैं। दीवालों को रंगना, सभी प्रकार के रंग···इत्यादि भी हमारी संस्कृति है। हमारा रहन सहन हमारी संस्कृति हैं और इसके कुछ पहलुओं को बदलना जरूरी है। संस्कृति जिस उच्च पहलू का आगे विकास किया जाना है उसे सामान्य भारतीय नागरिक तक पहुंचाना है। उसे आप जनता तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में एक छोटे से आर्ट आडिटोरियम, बन्द कमरे में सर्वोत्तम 'भरत नाटयम' कराने का कोई उपयोग नहीं है। महोदय इससे किसे लाभ होगा, इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन सभी पहलुओं को मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत लाना चाहिए और इसलिए हमने अब तक का शायद सबसे अधिक धनराशि इन क्षेत्रों के लिए आंकलित की है। हमें उम्मीद है कि देश में प्राप्त आदानों से हम ऐसी नीति तैयार करने में सफल हो जायेंगे जिससे यह लक्ष्य उपलब्ध कर लिए जायेंगे ।

अब हमारे एक दोस्त ने सदन में हो रही इस आलोचना के बारे में मुझे बताया है । कि हमने सरकारी क्षेत्र की अवहलेना की है (व्यवधान) मैं आंशिक रूप से अपने मित्र से सहमत हूं। परन्तु हमने इसकी अवहलेना नहीं की हैं। हां, पूर्व के कुछ राज्यों की अवहलेना की गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमलदत्त, क्या आपने इसे सुना ?

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं बहुत गम्भीर हूं। मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार हम सरकारी क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक धनराशि आबंटित की गई है जितनी इससे पहले कभी नहीं की गयी थी। महोदय, जब हम गैर सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं; तो हमारे जो दोस्त, गैर सरकारी क्षेत्र में रुचि रखते हैं वे गैर सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। वह बड़े उद्योगपति नहीं हैं, वह गैर-सरकारी क्षेत्र का बहुत कम प्रतिशत हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में भारी संख्या छोटे किसानों की है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यदि आप सरकारी क्षेत्र और छोटे किसानों को जोड़ना चाहते हैं तो यह हमारे पूंजी निवेश का बहुत बड़ा भाग होगा । उनके गैर सरकारी क्षेत्र में होने के कारण आप उन पर केवल लगाना पसन्द नहीं करेंगे । लेकिन तथ्य यह है कि छोटा किसान गैर सरकारी क्षेत्र में आता है । और यदि आप इसे पसन्द नहीं करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल में इसका राष्ट्रीकरण करने का यत्न कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम कोई योजना नहीं बना सकते हैं। जब हम दिल्ली आते हैं तो जो सर्वोत्तम होता है वह करते हैं (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि वे 91वीं योजना तैयार करें, । महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र को अब तक की सर्वाधिक धन-राशि आवंटित की गई है। एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सरकारी क्षेत्र हमारे विकास की कुंजी है। यह भारतीय उद्योग के लिए पथप्रदर्शक है और आज भी औद्योगीकरण की आगामी पीढ़ी में भारतीय उद्योग को ले जाने के लिए यह पथ प्रदर्शक बनेगा।

6.00 म० प०,

हमने कई मायनों में औद्योगिक विकास का एक चक्र पूरा कर लिया है। अब हमें एक और अधिक संवेदनशील चक्र पूरा करना होगा जिसमें गुणवत्ता, उत्पादकता और कुशलता को महत्व दिया जाए। जब कभी कोई उद्योग अक्षम बन जाता है, तो उसकी लागत पर आने वाला खर्च गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बलि चढ़ा कर पूरा किया जाता है। यदि सरकारी क्षेत्र किसी उद्योग को सौ करोड़ का घाटा होता है, तो किसी अन्य उत्पादक कार्यक्रम से सौ करोड़ कम कर दिये जाते हैं। इस तरह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से सौ करोड़ कम हो जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटा उठाने के लिए नहीं है । यह मजदूरों के लिए कोई सामाजिक उपाय नहीं हैं । हमें यह समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम दो हजार श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को रोजगार दिलाये रखने हेतु किसी संयंत्र को चालू रखने पर सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, ऐसे किसी संयंत्र पर, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, कोई धन बरबाद किये बिना हम उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें इस आधारभूत तथ्य को समझना चाहिए। यह आसान नहीं है परन्तु हमें यहां इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं कि हम लोगों, जो बहुत गरीब हैं, के धन का अपव्यय करें और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ये अभी सफेद हाथी बने रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अब तक आप पर बिल्कुल यही आरोप लगाते रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप अब इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : वास्तव में मैं पिछले सत्र में जब कुछ माननीय सदस्य मुझे से मिले तब उनके द्वारा किये गये अनुरोध के बारे में कह रहा था कि उनके कुछ उद्योगों का राष्ट्रीय-करण किया जाए।

श्री अमल दत्त : पुन सभी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है । आपकी प्रबन्ध व्यवस्था अकुशल होने के कारण ही आज वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुप्रबन्ध के कारण सभी संस्थान रुग्ण होते जा रहे हैं, उदाहरण के लिये हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनीड लिमिटेड को लीजिये।

श्री अमल दत्त : आप के इस्पात उद्योग की स्थिति क्या है ? आप करोड़ा रुपये का घाटा उठा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस तरह की रुग्णता किसी विशेष क्षेत्र में दिखाई देती है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि उनका कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप अपने सरकारी क्षेत्र को इतना बुरा क्यों मानते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है और यह आप की जिम्मेदारी है । आप नहीं कह सकते कि इनका कार्य-निष्पादन ठीक नहीं है, इसलिये इसे छोड़ दिय जाये । इसे दक्ष बनाइये ।

श्री राजीव गांधी : हमारे पास बहुत साधन होना चाहिये, जो हम पश्चिम बंगाल को इस क्षेत्र को बनाये रखने के लिये देते रहते हैं । हम ग्लुकोज इन्जेक्शन का एक बड़ा क्रेट आपके पास भेज देंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्येक को उसकी देय राशि मिलनी चाहिये ।

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी हम जिसको जो देना चाहिए, उसे देते हैं, जैसाकि हमने पिछली योजना में किया । मैं इस समय केवल पिछली योजना की बात कर सकता हूं । एक विशेष राज्य को बिजली के लिए बहुत अधिक आबंटन किया गया । उन्होंने शिकायत की कि बिजली की कमी है और उसका बहुत उत्पादन हो रहा है । मैं जानता हूं कि उस विशेष राज्य ने छठी योजना में लगभग हजारों करोड़ रुपये खर्च नहीं किये क्योंकि उन्होंने इसका बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया ।

श्री अमल दत्त : क्या आप समझते हैं कि पैसा था और उसे खर्च नहीं किया गया ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं इस संदर्भ में कुछ स्पस्टीकारण चाहूंगा । क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ । क्योंकि माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने यह प्रश्न पूछा ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इतने संकीर्ण क्यों होते हैं, जो समझते है कि हम केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया । माननीय सदस्य ने महसूस किया कि वहां पर ऐसा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान बाधा मत डालिये । कृपया उत्तेजित न होइये ।

श्री अमल दत्त : गत वर्ष आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रुपये नहीं दिये गये, कृपया उसे मत भूलिये ।

श्री राजीव गांधी : यही कारण है कि कुल राज्यों ने 300 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट लिया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : खड़े हुए—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, : श्री चौधरी—मैं अनुमति नहीं देता। मैं बहुत ही उदार रहा हूं अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त : मैं हर बार प्रधान मंत्री जी की बात नहीं काटना चाहता। परंतु मैं केवल इतना चाहता हू कि वे कुछ कहने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। दुर्भाग्यवश मैं प्रधान मंत्री द्वारा कुछ कहे जाने और अनभिज्ञता प्रकट किये जाने की सराहना नहीं कर सकता।

श्री राजीव गांधी : मुझे दुःख है कि मैं कुछ कहता हूं और उनकी अनभिज्ञता प्रकट कर देता हू।

श्री अमल दत्त : यह हमारी अनभिज्ञता नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। सवाल यह नहीं है। पैसा था ही नहीं। और यदि क्या पैसा नहीं था, तो यह उनका दोष है। जब हमने 3000 करोड़ रुपये मांगे हमें एकदम इन्कार कर दिया गया।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ कमी के बारे में कह रहे है। मैं किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं कह रहा था।

श्री अमल दत्त : आप पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर रहे थे।

श्री राजीव गांधी : स्पष्ट है कि उन्हें कुछ जानकारी है जो मुझे नहीं है।

श्री अमल दत्त : हम संसद सदस्य हैं। हमें जानने का अधिकार है। हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस राज्य के बारे मे कह रहे हैं। संसद में अस्पष्ट बयान देना कोई ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते हुए बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। आप अपनी उग्रता में बह जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्या आप अब थके नहीं ? हम इसे कहां तक चलने दे सकते हैं ? यह क्या हो रहा है ? इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव गांधी : यदि माननीय सदस्य शांत हो गये हैं, तो आपकी अनुमति से मैं अपना वक्तव्य जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय : अमल जी के साथ समस्या यह है कि वह हमेशा जोश में बह जाते हैं।

श्री राजीव गांधी : हमारा मुख्य ध्येय जैसा कि मैंने कहा है गरीबी दूर करना है। गरीबी दूर करने के लिये हमें जहां एक तरफ बड़ी परियोजनाएं कियान्वित करनी हैं, जो उत्पादक हों और अधिक उत्पादकता के माध्यम से धन पैदा करेंगे, जिसे हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर लगायें और उसका कुछ अंश उत्पादक कार्यक्रमों में पुनः लगायें। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं। हमने उन्हें मजबूत किया है और जहां हमने महसूस किया कि उनमें कुछ कमियां हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया है। हम आशा करते हैं कि सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विकास संबंधी अन्य परियोजनाओं से हमारा गरीबी स्तर सातवीं योजना के अन्त तक घटकर 25 प्रतिशत जायेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्री राजीव गांधी : आप ने देखा होगा कि गरीबी की रेखा के नीचे आने से सभा का एक भाग खुश है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कैसे कहते हैं ? मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इसमें क्या गलत है ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभा का दूसरा भाग गरीबी रेखा के ऊपर जाने के लिये जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : गरीबी रेखा के नीचे जाने आदि के सम्बन्ध में उनके आंकड़ों पर हम कदापि ही विश्वास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधान मंत्री जी ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : इस योजना में हमने अब तक सब से अधिक श्रमिक दिन पैदा किये हैं। हमारा अनुमान है कि इस योजना के दौरान 400 लाख नौकरियां बनाई जायेंगी।

श्री अमल दत्त : ये सब अनुमान ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इससे आप को आघात पहुंचता है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या आप जानते हैं कि गरीबी दूर होने से कुछ लोग दुखी हैं नौकरियों के अवसर पैदा होने से कुछ लोगों को दुख होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री अमल दत्त : केवल हम लोग ही आप की सहायता करेंगे। दूसरी तरफ के लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसे सद्भावना से देखिए।

श्री अमल दत्त : आपसे पूर्व के प्रधान मंत्री ने इस बात को तब महसूस किया जब हमने उनकी सहायता की।

प्रो० एम० जी० रंगा : आप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभकारी बनाकर सहायता कर सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं वह स्वीकार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। हम आज उनकी वजह से ही यहां आ सके हैं। उन्होंने देश को दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। यही धारणा है कि देश ने हमें चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः हमारी सबसे बड़ी समस्या सातवीं योजना को पूरा करने के लिए साधन जुटाना होगा और हमें इस पर केवल अधिक साधन जुटाने की दृष्टि से, जिसके लिए हमें भरसक प्रयास करना ही है, विचार करना बल्कि वह भी देखना चाहिए कि हम अपने साधनों का किस प्रकार अधिक कुशालता से उपयोग कर सकते हैं, चाहें वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कोई उद्योग विशेष हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कुशलता का पहलू सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि लोगों की विकास की अपेक्षा को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिमतम उपयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हम सब में दृढ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि इस कार्य में विपक्ष के भी कुछ सदस्य हमारी सहायता करेंगे। हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा निष्ठावान बनना पड़ेगा, देश के प्रति, अपने मूलभूत मूल्यों के प्रति कुछ प्रतिबद्धता रखनी होगी, हमने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए कुछ निस्वार्थ भाव अपनाना पड़ेगा। यह केवल एक वर्ग अथवा दूसरे वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह कार्य हम सब को मिलकर करना है। यह एक सहकारी प्रयास होना चाहिए, न केवल इस सदन के भीतर बल्कि इसमें देश के 74 करोड़ 60 लाख लोगों को साथ लेना होगा। इसके लिए हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा और भारत के प्रति, गांधी जी के शब्दों में स्वदेशी के प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त करनी होगी, वचनबद्धता निभानी होगी। स्वदेशी के मायने आज काफी बदल गए हैं। अब यह केवल उन एक या दो उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, जो 40 वर्ष पूर्व स्वदेशी थे। वह हमारे विकास का एक अंग है। परन्तु मूलभूत आवाज, जो गांधी जी ने स्वदेशी के लिए उठाई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बात हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ही हमारी योजनाओं को अपेक्षित सफलता मिलेगी।